



चीन पर दबाव बढ़ाना चाहिए

विश्व समुदाय को चीन पर दबाव बढ़ाना चाहिए, जिसकी नीयत ठीक नहीं दिख रही। लाखों जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि वायरस किस तरह इंसानों तक पहुंचा। चीन न तो लीकेज की बात मान रहा है और न ही पूरी जांच करने दे रहा।

शांति शाह।।

दुनिया कोविड-19 को काबू करने के उपाय ढूंढ रही है, उधर इस महामारी के फैलने की वजह पर जमी धुंध छंटने का नाम नहीं ले रही। दिसंबर 2019 में चीन ने अपने यहां पहले मामले की पुष्टि की थी। उसके बाद चीन और कई दूसरे देशों के वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना वायरस चमगादड़ से इंसानों तक पहुंचा। बीच-बीच में लैब में प्रयोग के दौरान वायरस लीक होने की आशंका भी जताई गई, लेकिन तब अधिकतर वैज्ञानिकों ने उसे तवज्जो नहीं दी। इस बीच चीन एक अहम जानकारी छिपाए रहा। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से पता चला है कि वूहान में महामारी शुरू होने से पहले नवंबर 2019 में वूहान इंस्टिट्यूट ऑफ वायरॉलजी के 3

रिसर्चर गंभीर रूप से बीमार पड़े और उनमें कोविड-19 जैसे लक्षण थे। वूहान इंस्टिट्यूट पर वैसे भी वैज्ञानिकों की नजरें रहीं हैं। वहां 'I' के विषाणुओं पर अध्ययन हुए थे। लाइव वायरस पर भी प्रयोग वहां चलते रहते हैं। वहां की टॉप साइंटिस्ट डॉ. शी जेंगली ने कृत्रिम वायरस बनाने की पढ़ाई की थी अमेरिका में। डॉ. शी के नेतृत्व में युन्नान प्रांत की एक खदान से चमगादड़ों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें कोरोना खानदान के वायरस मिले। उस खदान में 2012 में छह मजदूर अचानक बीमार पड़े थे। डॉ. शी ने माना है कि उनकी लैब में कोरोना खानदान के विषाणुओं पर प्रयोग हो रहे थे। देखा जा रहा था कि विषाणु अपने स्पाइक प्रोटीन को इंसानी कोशिका



के एंजाइम पर चिपका सकता है या नहीं। डॉ. शी का दावा है कि ऐसे प्रयोग भविष्य में आ सकने वाली महामारियों का अंदाजा लेने के लिए किए जा रहे थे। दुनिया के कई वैज्ञानिक ऐसे प्रयोगों को पूरी तरह गलत नहीं मानते, लेकिन वे लैब से लीकेज का सवाल उठा रहे हैं। चीन न तो लीकेज की बात मान रहा है और न ही पूरी जांच करने दे रहा। इस साल विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो टीम चीन गई, उसे भी वूहान लैब के पूरे रिकॉर्ड नहीं दिखाए गए। इस बीच, ब्रिटेन और नॉर्वे के

वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वूहान लैब में लीकेज से भी कहीं ज्यादा खतरनाक मामला है। वहां कृत्रिम कोरोना वायरस बनाए गए। फिर रेट्रो जेनेटिक इंजीनियरिंग से उनको नैचरल स्वरूप देने की कोशिश की गई ताकि किसी को शक न हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को लैब लीक के पहलू की 90 दिनों में जांच करने को कहा है। विश्व समुदाय को चीन पर दबाव बढ़ाना चाहिए, जिसकी नीयत ठीक नहीं दिख रही। लाखों जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि वायरस किस तरह इंसानों तक पहुंचा। यह पता चलने पर ही भविष्य के लिए सुरक्षा उपाय किए जा सकेंगे, इंसान और जानवर के संपर्क के दायरे से लेकर प्रयोगशालाओं तक।

भौतिकतावादी

अशोक बोहरा। अभी भी समय है, हम अपने सभी प्रकार के भय को बाहर फेंक दें और अपनी सनातन संस्कृति को स्वाध्याय के माध्यम से जानने की कोशिश करें क्योंकि आज के भौतिकतावादी समय में यह ज्ञान देने कोई दूसरा विवेकानंद नहीं आयेगा। विष्णु पुराण में कहा गया है कि यन्तु मेघेरु समुत्प्लुष्टं वारि तत्प्राणिनां द्विज [पुष्पात्पौषधयः सर्वा जीवनायामृतं हि तत्]। अर्थात् जो जल मेघों द्वारा बरसाया जाता है, वह प्राणियों के लिए अमृत स्वरूप है और वह जल मनुष्यों के लिए औषधियों का पोषण करता है। तभी तो कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले वर्षा जल में इतनी जवनादायिनी शक्ति है कि यह सीपी में गिर जाए तो मोती बन जाता है, केले के पत्ते पर गिरता है तो कपूर बन जाता है और यदि सांप के मुँह में गिरे तो विष बन जाता है।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

हिंदू फासीवाद नहीं आया

2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से भारत कम धर्मनिरपेक्ष हुआ है। यहां उदारता में भी कमी आई है। इसके बावजूद यह फासीवादी हिंदू राष्ट्र नहीं बना है, जैसा कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं। याद कीजिए कि जब 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी को भारी जीत मिली, तो उसके साथ आंध्र प्रदेश में हुए चुनाव में वार्डएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी को विजय मिली। रेड्डी ईसाई हैं। 49 फीसदी वोट पाकर उन्होंने 175 में से 151 सीटों पर कब्जा किया, जबकि बीजेपी को आंध्र चुनाव में 0.84 फीसदी वोट मिले और वह एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसी से हिंदू फासीवाद के दावे की पोल खुल जाती है। नहीं तो, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि सिर्फ 20 फीसदी दलित, आदिवासी और मुसलमानों को हाल में किसी तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसका कि पूरे में दावा किया गया है। जिस तरह से एनएसएसओ सर्वे में कंजम्पशन को कम बताया गया, उसी तरह से पूरे में भेदभाव को कम और सहिष्णुता को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया होगा। मुझे उम्मीद की रोशनी दिखती है। इसकी बुनियाद सत्ता की खातिर धुर विरोधियों के बीच गठजोड़ की संभावना है। देश में विविधता और सहिष्णुता की यह कहीं बेहतर गारंटी है, जो नैतिकता की दुहाई या संविधान संशोधन से संभव नहीं है।

सर्वे के नतीजों से लगता है कि भले ही हमारा समाज जातीय और धार्मिक आधार पर बंट हुआ है, लेकिन वह सहिष्णु भी है। यह हिंदू राष्ट्रवादी समाज नहीं है, जिसका डर आलोचकों को रहा है।

सहिष्णु भारत का सच

स्वामिनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर।।

प्यू रिसर्च सेंटर के 'भारत में धर्म, सहिष्णुता और अलगाव पर सर्वे' में दावा किया गया है कि 90 फीसदी भारतीय धार्मिक तौर पर सहिष्णु हैं। वे अपने धर्म और जाति से बहुत गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं और दूसरों के साथ घुलने-मिलने को लेकर उनके अंदर एक हिचक है। सर्वे में शामिल होने वाले ज्यादातर लोगों ने यह भी कहा कि धार्मिक प्रथाओं को लेकर उन्हें आजादी मिली हुई है और वे दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं। बहुसंख्यक 20 फीसदी लोगों को ही हाल में जातीय या धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। सर्वे के नतीजों से लगता है कि भले ही हमारा समाज जातीय और धार्मिक आधार पर बंट हुआ है, लेकिन वह सहिष्णु भी है। यह हिंदू राष्ट्रवादी समाज नहीं है, जिसका डर आलोचकों को रहा है।

क्या पूरे के नतीजे विश्वसनीय हैं? सर्वे बताता है कि अधिकतर लोग अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच शांति या धर्मांतरण के खिलाफ हैं। दूसरे धर्मों और जातियों में उनके बहुत कम दोस्त हैं या कोई दोस्त नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं, जो नहीं चाहते कि दूसरे धर्मों के लोग उनके पड़ोसी बनें। सहिष्णुता को लेकर जो वैश्विक समझ है, यह उससे मेल नहीं खाता। भारत में उप-जाति, धर्म, क्षेत्र, पेशा और ऐसे ही कई



अन्य आधारों पर समाज हजारों हिस्सों में बंट हुआ है। इनमें से कई चुनावी वोट बैंक में बदल चुके हैं। इसी वजह से कई 'मिनी-पॉलिटिकल' पार्टियां वजूद में आई हैं और इनमें से कई तो सिर्फ स्थानीय समूहों की नुमाइंदगी करती हैं। गठबंधन राजनीति का मतलब है कि आप दूसरे सभी दलों के साथ मोर्चा बनाने को तैयार रहते हैं। आज जो दुश्मन है, वह कल को आपका दोस्त बन सकता है और यही राजनीतिक शक्ति की कुंजी बनती है। हाल में इसकी सबसे अच्छी मिसाल शिवसेना है, जिसने बीजेपी को छोड़कर सेक्युलर पार्टियों के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। इन राजनीतिक मजबूरियों की वजह से भारत आगे भी विविधता भरा लोकतंत्र बना रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) सभी हिंदू वर्गों को बीजेपी के पीछे

गोलबंद करना चाहता है। इस मामले में पूरे रिसर्च का सर्वे एक दिलचस्प संकेत करता है। वह बताता है कि अधिकतर जातीय और धार्मिक समूह अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि हिंदू पहचान में घुल-मिलकर उनकी यह आइडेंटिटी खत्म हो जाए। सत्ता हासिल करने के लिए विरोधियों को लुभाना और उन्हें खरीदना वैचारिक शुद्धता के मुकाबले बेहतर फॉर्म्युला साबित हुआ है। इसी वजह से बीजेपी जहां हिंदी पट्टी में गोकशी पर सख्ती करती है वहीं गोवा और पूर्वोत्तर में उसे इससे कोई परेशानी नहीं है। इन राज्यों में ईसाई उसके सहयोगी हैं। यह देश की सेक्युलर डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। कुछ जाने-माने राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारत अपने मिजाज में हिंदू राष्ट्र बन चुका है, भले ही घोषित तौर पर ऐसा न हो। जिन राज्यों में बीजेपी का शासन है, वहां हिंदू गैंगों को पुलिस का मौन समर्थन हासिल है। सांप्रदायिक आधार पर लिविंग के मामले बढ़े हैं। इसलिए कुछ जाने-माने विश्लेषक भी कहते हैं कि भारत में आधा फासीवाद आ चुका है। पूरे रिसर्च के सर्वे में जो सहिष्णु भारत दिखाया गया है, वे उसे सच नहीं मानते। यहां हम पूरे की ईमानदारी और उसकी तकनीकी क्षमताओं पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन यह भी सच है कि सर्वे में अक्सर भारतीय झूठ बोलते आए हैं।

सूंडीकू नवताल-5294		सूंडीकू कवताल-5293 का तल	
2	3	8	4
9	8	2	6
1	3	6	9
4	3	2	1
8			8
4	7	5	3
3	7	5	4
2		8	1

अपना ब्लॉग

ऐसी दिक्कत पूरे में भी होगी

मोहन। पिछले साल सरकार के प्रस्तावित नेशनल रजिस्टर ऑफ सितिजंस के खिलाफ शाहीन बाग और दूसरी जगहों पर प्रदर्शन के बाद कई सरकारी सर्वे करने वालों को भागना पड़ा, जबकि कुछ की गांव वालों ने पिटाई कर दी। उन्हें डर था कि सर्वे करने वाले जो सवाल पूछ रहे हैं, उससे उनकी नागरिकता खतरे में पड़ सकती है। कंजम्पशन यानी खपत पर सबसे हालिया सर्वे बताता है कि इसमें 2011-12 और 2017-18 के बीच गिरावट आई। यह बात हैरान करती है क्योंकि उस दौरान जीडीपी में 7 फीसदी सालाना की बढ़ोतरी हुई थी। इसका कारण यह हो सकता है कि जिनका सर्वे किया गया, उन्होंने जानबूझकर इस बारे में झूठ बोला। ऐसी दिक्कत पूरे में भी होगी। धार्मिक आधार पर निशाना बनाए जाने के डर से लोगों ने सही जवाब नहीं दिए होंगे। इसी वजह से चुनाव के वक्त अलग-अलग एजेंसियों के ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के नतीजों में काफी अंतर होता है और अक्सर वे सचाई से भी काफी दूर होते हैं।

